काम का दबाव

विश्व व्यापार संगठन ने 'बर्नआउट' को मानसिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में चिह्नित किया है. कार्यस्थल के लगातार दबाव से समुचित ढंग से छुटकारा नहीं पाने के कारण 'बर्नआउट' की स्थिति पैदा होती है. शोधार्थियों का कहना है कि यह आधुनिक समाज के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी उन समस्याओं में है, जिनके बारे में बहुत चर्चा हुई है. कुछ पेशेवर समूहों में तो 'बर्नआउट' की पैठ 69 फीसदी तक है. इसके मुख्य लक्षणों में ऊर्जा की कमी या थकान, अपने काम से मानसिक दूरी बढ़ना या उसके प्रति नकारात्मक भाव आना तथा पेशेवर क्षमता में कमी प्रमुख हैं. आखिरकार इस महीने समस्या के रूप में चिह्नित होने के बाद इससे परेशान लोग अब चिकित्सकीय सहायता और सलाह ले सकेंगे. अर्थव्यवस्था और नगरीकरण के तीव्र विस्तार के कारण भारत में भी विभिन्न पेशेवर समूहों की संख्या और प्रतिस्पर्धा का दबाव निरंतर बढ़ रहा है. एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वॉर्टरली में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक, हमेशा काम पर लगे रहने की संस्कृति लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को तो प्रभावित कर ही रही है, इससे काम की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है. रहन-सहन के क्षेत्र में सिग्ना द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में भी भारतीय पेशेवरों पर तनाव के नुकसानदेह असर को रेखांकित किया गया है. निर्धारित समय से अधिक काम करने से भले ही पेशेवरों को अधिक भत्ते या प्रोन्नति जैसे लाभ मिले हों, परंतु मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब हुआ है. वर्ष 2015-16 के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया था कि लगभग 15 फीसदी वयस्कों को चिकित्सकीय सलाह और मदद की दरकार है. एक चिंताजनक संकेत यह भी है कि पुरुषों से कहीं अधिक कामकाजी महिलाएं ज्यादा तनाव में पायी गयीं. बेहतर काम करने का दबाव और नौकरी से निकाले जाने का डर इस तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है. सर्वेक्षण के अनुसार, समस्या के समाधान के लिए प्रबंधन या रोजगारदाता की ओर से किये गये इंतजाम से कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं. संतोषजनक है कि कुछ बड़ी कंपनियां इस दिशा में प्रभावी प्रयास कर रही हैं तथा सिग्ना सर्वेक्षण ने भारत को उन देशों की सूची में रखा है, जहां हालात बेहतर हो रहे हैं. इसी सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि 10 में से नौ भारतीय तनाव से ग्रस्त हैं. विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक, भारत में आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास के मामले भी हर साल बढ़ रहे हैं. इन समस्याओं के बारे में जागरूकता कम होने के कारण भी मुश्किल आती है. परेशान व्यक्ति परिवार, मित्रों और सहकर्मियों से इस बाबत चर्चा करने में हिचकता है. उम्मीद है कि राष्ट्रीय नीति में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से स्थिति सुधरेगी. प्रशिक्षित सलाहकारों की संख्या बढ़ाने और कंपनियों द्वारा उनका सहयोग लेने की दिशा में गंभीरता से पहल की जानी चाहिए. मानसिक स्वास्थ्य को बहाल रखने के लिए काम के साथ आराम और रचनात्मक गतिविधियों के संतुलन पर जोर देना होगा.

निर्धारित समय से अधिक काम करने से भले ही पेशेवरों को अधिक भत्ते या प्रोन्नति जैसे लाभ मिले हों, परंतु मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब हुआ है.

राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार
awadheshkum@gmail.com

अब जब चुनाव खत्म हो गया है, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश का गंभीरता से विचार करना जरूरी है. क्या राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी देश के लिए प्रमुख मुद्दा होना चाहिए या नहीं? पूरे चुनाव के दौरान कुछ लोगों का तर्क था और आज भी है कि राष्ट्रवाद मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह भावनाओं को भड़काने का विषय है. सैन्य पराक्रम पर राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए, इससे उग्र राष्ट्रवाद भड़कता है. सुरक्षा को चुनाव का मुद्दा बनाना असली मुद्दों से ध्यान भटकाना था. पाकिस्तान के खिलाफ चुनाव में बोलना लोगों को गुमराह करना था. क्या वाकई चुनाव में ये सब मुद्दे उठने ही नहीं चाहिए थे? यह सच है कि ये सारे मुद्दे चुनाव में भाजपा के पक्ष में जाते दिखते थे और गये भी. लेकिन देश ने दूसरी पार्टियों को ये मुद्दे उठाने से रोका तो था नहीं. यह विषय चुनाव तक ही सीमित नहीं है. इस पर हमारे यहां लगातार बहस चलती रहती है.

हम एक अजीब संस्कारों वाले देश हैं. यहां राष्ट्रवाद, पराक्रम, सुरक्षा आदि से एक बड़े वर्ग के अंदर संस्कारगत वितृष्णा है. दुनिया के प्रमुख देशों की स्थिति उलट है. हमारा पड़ोसी चीन कम्युनिस्ट शासन वाला देश है. किंतु चीनी राष्ट्रवाद कम्युनिज्म पर भारी है और इसी कारण वह संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों को पाता है. राष्ट्रीय सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि है तथा राष्ट्र की सीमाओं की उसकी जो कल्पना है, उस पर वह टस से मस होने को तैयार नहीं. तिब्बत में हिमालय तक रेल पहुंचा देने का असाधारण करनामा उसने कैसे कर दिखाया? नाभिकीय मिसाइलों का जखीरा उसने हमारे पास हिमालय में बिछा दिया है. डोकलाम भूटान का भाग है, पर वह दावा करता है और उसे साबित करने के लिए उसने किस तरह की सैनिक जिद की, यह सामने है. अगर हमारे पास सैन्य ताकत नहीं होती और राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ निर्णय नहीं करता, तो भूटान भाग वाले डोकलाम से चीन हटता?

सोवियत संघ के विघटन के बाद अनेक विश्लेषक रूस के दुर्बल, जर्जर और दयनीय देश होने की भविष्यवाणी कर चुके थे. अपनी बुरी दशा से उबरने के लिए रूस के नेतृत्व ने रूसी राष्ट्रवाद की चेतना जागृत की और आज वह महाशक्ति को चुनौती दे रहा है. मलेशिया इस्लामी देश है. कर्ज से देश को बाहर निकालने के लिए महाथिर मोहम्मद को राष्ट्र की बात करनी पड़ी और लोग दान देने के लिए आगे आने लगे. इस्राइल तो राष्ट्रवाद के दम पर ही अपना अस्तित्व बनाये हुए है. आप अमेरिका से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक नजर दौड़ा लीजिए, सब अपने यहां राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और यह चुनाव में मुद्दा रहता है. आतंकवाद के उभार के बाद तो हर देश में पार्टियों को बताना पड़ता है कि इसके संदर्भ में उनकी सुरक्षा नीति क्या है. दुनिया के सभी प्रमुख देशों में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ऐसी विकृत धारणा नहीं है, जैसा हमारे यहां है. यह भारत नामक इस राष्ट्र की त्रासदी है कि यहां आनुवंशिकी में ही ऐसे कुछ विचार रहे हैं. यह अकेला देश है, जहां अपने राष्ट्रीय हीरो की चर्चा करने को उग्र-राष्ट्रवाद या फासीवाद साबित किया जाता है.

चुनाव को राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, कश्मीर मुद्दे आदि से वंचित कर देने की सोच कतई सकारात्मक नहीं कही जा सकती. ये मुद्दे शाश्वत हैं और देश की सामूहिक भावना के साथ इसका जुड़ा रहना आवश्यक है.

भारत की गुलामी के पीछे भी यह प्रमुख कारण रहा है. जब 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा था, तो जितने लोग सिराजुद्दौला के साथ लड़नेवाले थे, उससे कई गुणा ज्यादा लोग मैदान के बाहर तमाशा देख रहे थे. किसी ने नहीं सोचा कि इससे देश के भाग्य का फैसला होनेवाला है. अगर वे लोग थोड़ा भी पराक्रम दिखाते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक वहीं खत्म हो जाते. ऐसा नहीं हुआ और देश गुलाम हो गया. और भारतीय सिपाहियों ने अपने शासकों के आदेश पर भारत के लोगों पर अत्याचार किये. अंग्रेजी शासनकाल में उनकी पुलिस में ज्यादातर भारतीय ही थे, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों या विरोध की आवाज उठानेवालों पर गोलियां-लाठियां चलायीं. नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने पराक्रम दिखाया, सैन्य संगठन बनाया और युद्ध लड़ा. उनके 24 हजार से ज्यादा जवान शहीद हुए. इसी देश में उनका विरोध भी हुआ. आजादी में आजाद हिंद फौज के योगदान को इतिहास में वैसी जगह नहीं मिली, जैसी जॉर्ज वाशिंगटन और उनके साथियों को अमेरिका में मिलती है.

यह अच्छा संकेत है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय मानस में थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन संस्कारगत दोष जा नहीं रहे है. इसलिए कुछ लोग ऐसा प्रचारित करते हैं कि राष्ट्रवाद, पराक्रम, सुरक्षा जैसे विषयों को उठाकर लोगों की भावनाएं भड़कायी जा रही हैं. पाकिस्तान हमारे यहां आतंकवाद प्रायोजित करता रहा है. लंबे समय बाद देश ने 2015 में म्यांमार में तथा 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत के बदलते संस्कार का परिचय दिया. फरवरी 2019 में युद्धक विमानों से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी ने इस बदलाव को ज्यादा सुदृढ़ किया और राष्ट्रवाद व पराक्रम का यह संयोग लोगों को रोमांचित करता रहा. साल 1971 के पहले भारत ने इस तरह कोई युद्ध कब जीता? चुनाव में इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए थी, यह समझ से परे है. गुन्नार मिर्डल ने भारत को सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा यूं ही नहीं दी थी. भारत की वह छवि बदल रही है, तो यह चुनाव अभियान में गूंजित होना ही था. दूसरे दल भी इसे उठा सकते थे. अगर सरकार ने निर्णय किया, तो उसका समर्थन करने एवं पराक्रम को सराहने में विपक्ष संकोच नहीं करता, तो माहौल दूसरा होता.

चुनाव अभियान में नेताओं को जनता के सामने सबसे ज्यादा बातें रखने का अवसर मिलता है. ऐसे अवसर को राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, कश्मीर आदि से वंचित कर देने की सोच कतई सकारात्मक नहीं कही जा सकती. ये मुद्दे शाश्वत हैं और देश की सामूहिक भावना के साथ इसका जुड़ा रहना आवश्यक है. इससे जो वातावरण बनता है, वह सभी क्षेत्र में सक्रिय लोगों को राष्ट्र का ध्यान रखते हुए काम करने तथा आवश्यकता पड़ने पर पराक्रम दिखाने के लिए प्रेरित करता है. हमारे सुरक्षा बलों का भी हौसला बढ़ता है कि राजनीतिक पार्टियां एवं आम जनता भी उनके पराक्रम को मुद्दा बना रहे हैं. दुनिया के प्रमुख देश इसी रास्ते आगे बढ़े हैं. इसी तरह कश्मीर के समाधान का विषय राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए. लंबे समय से इसका मुद्दा न बनना दुर्भाग्यपूर्ण था. कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो उसे सामान्य बनाना चुनाव मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए था?

अच्छा है कि धीरे-धीरे अब आम जनता की समझ भी इन सवालों की दिशा में विकसित होने लगी है.

चीन से सीखें, आबादी रोकें

आरके सिन्हा
सांसद, राज्यसभा
rkishore.sinha@sansad.nic.in

अब देश को अपनी आबादी पर नियंत्रण करने के लिए एक व्यापक नीति बनानी ही होगी. इस मसले को राजनीति और धार्मिक आस्थाओं से ऊपर उठकर देखना ही उचित होगा. सबको याद रखना होगा कि देश बचेगा, तो ही धर्म और राजनीति बचेगी.

सत्रहवीं लोकसभा चुनाव की सारी प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने अपना कामकाज फिर से शुरू कर दिया है. यूं तो इस सरकार को देश हित में बहुत से अहम निर्णय लेने हैं, यदि सरकार देश में आबादी को रोकने के लिए भी कोई ठोस नीति लेकर आये, तो इसका स्वागत ही होगा. इस मसले पर अविलंब निर्णय लेने की आवश्यकता है. हमने अपनी आबादी को काबू में करने में देरी कर दी है. इसके पीछे लंबे समय तक सत्तासीन पार्टियों की वोट की राजनीति ही जिम्मेदार थी. तब एक खास समुदाय को खुश करके उनके वोट हथियाने के लिए सत्ताधारी नेताओं ने देश की तेजी से बढ़ती आबादी को रोकने के संबंध में सोचा ही नहीं. इसी सोच के कारण उस खास समाज को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. वह विकास की दौड़ में पिछड़ गया है.

योग गुरु बाबा रामदेव ने भी देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाये जाने का पक्ष लेते हुए हाल ही में कहा कि दो बच्चों के बाद पैदा होनेवाले बच्चे को मताधिकार, चुनाव लड़ने के अधिकार और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए. भारत को दिल से चाहनेवाला हर नागरिक बाबा रामदेव की सलाह के साथ खड़ा होगा. मैं यह जरूर कहूंगा कि बच्चों को मताधिकार से क्यों वंचित किया जाये? क्यों न तीन बच्चों को पैदा करनेवाले पति-पत्नी को मताधिकार से वंचित करने की सजा दी जाये. रामदेव ने देश के सामने उस मसले के हल को पेश किया, जिससे देश जूझ रहा है. बढ़ती हुई आबादी देश के लिए समस्या है. बढ़ती आबादी को विकास का पूरा लाभ कोई भी सरकार कैसे दे सकती है. हमारी विकास परियोजनाओं की सफलता के रास्ते में सदैव आबादी एक बड़े अवरोध के रूप में खड़ी हो जाती है.

जहां देश अपनी अधिक आबादी को लेकर चिंतित है, वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा रामदेव की सलाह के जवाब में कहा- 'लोगों को असंवैधानिक बातें कहने से रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन रामदेव के विचारों पर बेवजह ध्यान क्यों दिया जाता है?' ओवैसी ने ट्वीट किया, वह योग कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए अपना मताधिकार खो देंगे, क्योंकि वह तीसरी संतान हैं. ओवैसी हर मसले पर सियासत करने से तो बाज ही नहीं आते. क्या ओवैसी को यह दिखाई नहीं देता है कि सारा देश जनसंख्या विस्फोट के कारण कितना कमजोर हो रहा है?

बाबा रामदेव कमोबेश वही कह रहे हैं, जिसे चीन ने वर्षों पहले करके दिखा भी दिया. चीन ने एक बच्चे से अधिक पैदा करनेवाले अपने नागरिकों को बहुत सी सुविधाओं से वंचित कर दिया था. बाबा रामदेव भी कह रहे हैं कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करनेवालों से सभी सरकारी सुविधाएं छीन लेनी चाहिए, यहां तक कि मतदान का अधिकार भी. चीन ने भी अपनी बढ़ती आबादी रोकने के लिए यही किया. वहां 'एक दंपति एक बच्चा' को सख्ती से लागू किया गया. भारत में भी 'हम दो, हमारा एक' का सिद्धांत अगले पचास वर्षों तक लागू हो, जब तक कि आबादी घटकर सौ करोड़ से कम नहीं हो जाती है.

जहां जनसंख्या विस्फोट के कारण देश की नींद हराम हो जानी चाहिए थी, वहीं कुछ ज्ञानी जनसंख्या को एक वरदान के रूप में देखते हैं. वे यह मानते हैं कि जितने अधिक लोग होंगे, उतना ही अधिक काम हो सकेगा और उसी अनुपात में आय भी बढ़ेगी. हालांकि, यह सोच अतार्किक है. बेरोजगारी, अशिक्षा और अपराध का सीधा संबंध तेजी से बढ़ती आबादी से है. अब हमारे लिए अपनी जनसंख्या का प्रबंधन करना असंभव सा हो चुका है. बेरोजगारी का आलम यह है कि तीन-चार हजार रुपये मासिक पर भी पढ़े-लिखे शिक्षित नौजवान पढ़ाने को तैयार हो जाते हैं. इंजीनियर को 15 हजार मिल जायें, तो गनीमत है. मजदूर-किसान अमानवीय स्थितियों में जीने को मजबूर हैं. इसे ही सस्ता श्रम कहकर विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित किया जाता है.

भारत में 2011 में जनगणना हुई थी. उसी समय भारत की आबादी 1.20 करोड़ से अधिक हो चुकी थी. हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर थे. पर अगर हमने तुरंत कठोर कदम नहीं उठाये तो साल 2025 तक हम चीन को भी मात दे चुके होंगे. भारत के साथ एक दिक्कत यह भी है कि असम और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ सूबों में हर साल लाखों बांग्लादेशी अवैध रूप से घुस जाते हैं. एक अनुमान के मुताबिक, भारत में तीन-चार करोड़ बांग्लादेशी नागरिक बस चुके हैं. ये देश के हर शहर में छोटा-मोटा काम करते हुए देखे जा सकते हैं. ये आपराधिक मामलों में भी लिप्त रहते हैं. कुछ वर्ष पहले राजधानी के विकासपुरी में गैर-कानूनी तरीके से भारत में आकर बस गये बांग्लादेशी गुंडों ने डॉक्टर पंकज नारंग का कत्ल कर दिया था. राजधानी के यमुना पार में बांग्लादेशियों का आतंक बढ़ता ही चला जा रहा है.

दरअसल, अब देश को अपनी आबादी पर नियंत्रण करने के लिए एक व्यापक नीति बनानी ही होगी. इस मसले को राजनीति और धार्मिक आस्थाओं से ऊपर उठकर देखना ही उचित होगा. सबको याद रखना होगा कि देश बचेगा, तो ही धर्म और राजनीति बचेगी.

बोधि वृक्ष

स्वास्थ्य के लिए

जब पेट में पाचन प्रक्रिया चल रही होती है, तब कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया लगभग रुक जाती है. अगर आप दिनभर खाते ही रहते हैं, तो कोशिकाओं में अशुद्धियां लंबे समय तक बनी रहती हैं, जो फिर एक अवधि के बाद शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं. आंतों से मल बाहर निकलने की प्रक्रिया भी तब सही ढंग से नहीं होती, क्योंकि बड़ी आंत में, एक ही समय पर आने की बजाय, अलग-अलग समय पर कचरा आता ही रहता है. यौगिक व्यवस्था में हम ऐसा कहते हैं कि एक भोजन के बाद दूसरा भोजन करने में कम से कम छह से आठ घंटों का अंतर होना चाहिए. अगर यह संभव न हो, तो कम-से-कम पांच घंटों का अंतर तो होना ही चाहिए. अगर बड़ी आंत साफ नहीं रहती, तो आप समस्याओं को न्योता दे रहे हैं. योग में यह कहा जाता है कि गंदी आंत और मनोवैज्ञानिक अशांति एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं. अगर आप की बड़ी आंत साफ नहीं है, तो आप अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते. आयुर्वेद तथा सिद्ध जैसी भारत की पारंपरिक औषधि पद्धतियों में किसी भी रोगी की बीमारी चाहे जो हो, वे पहले आप की पाचन व्यवस्था को शुद्ध करना चाहेंगे, क्योंकि एक खराब बड़ी आंत आप की अधिकतर समस्याओं की जड़ हो सकती है. आजकल लोग जिस तरह से खा रहे हैं, अपनी बड़ी आंत को स्वच्छ रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है. लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ दो बार अच्छी तरह भोजन करते हैं और बीच में कुछ नहीं खाते, जैसे हम सामान्य रूप से आश्रम में करते हैं या अगर हम बहुत ज्यादा कामों में लगे हैं, तो हम एकाध फल खा सकते हैं, तो आप की बड़ी आंत हमेशा स्वच्छ रहेगी. जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, यौगिक पद्धति के अनुसार एक भोजन के बाद दूसरा भोजन करने में कम से कम छह से आठ घंटों का अंतर होना चाहिए. अगर ऐसा न हो पाये, तब कहीं जाकर कम-से-कम पांच घंटों का अंतर रखना चाहिए. इससे कम का अंतर है, तो समझ लीजिए कि आप अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं.

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

आपके पत्र

राष्ट्रवादी विचारधारा को मिला ज्यादा महत्व

भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में एनडीए की फिर सरकार बनी. इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई गैर कांग्रेसी पार्टी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही हो. एक समय ऐसा लगा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से कांग्रेस के प्रदर्शन में कोई सुधार होगा, परंतु ऐसा हो सका. अभी भले ही कांग्रेस पार्टी के अंदर पद त्याग और इस्तीफे की बात चल रही हो, परंतु उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शब्द और भाषण किसी भी चुनाव में बहुत महत्व रखते हैं. किसी स्वच्छ चरित्र वाले व्यक्ति को अपशब्द कहने के बजाय अगर कांग्रेस विकास के मुद्दों पर ध्यान देती तो शायद चुनाव के परिणाम में कोई परिवर्तन के आसार दिखाई देते. इस चुनाव परिणाम से यह तो तय हो गया है कि लोगों ने धर्म और जाति की भावनाओं से ऊपर उठ कर राष्ट्रवादी विचारधारा को ज्यादा महत्व दिया है, जो सराहनीय है.

शुभम गुप्ता, नावागढ़, धनबाद

दूसरी पारी से आशाएं

किसी रेखा को बिना मिटाये छोटा दिखाने के लिए उसके बराबर में एक बड़ी रेखा खींचना होती है. ठीक इसी तरह देश की पिछली सभी सरकारों के कार्यों, प्रगति और विकास को छोटा दिखाने के लिए भी वर्तमान मोदी सरकार को अपने कार्यों, विकास और प्रगति की एक लंबी रेखा जरूर खींचनी होगी, जो शायद मोदी सरकार अब चाहती है. यह इतना आसान कार्य भी नहीं है क्योंकि सिर्फ कहने, चाहने और करने में बड़ा अंतर होता है. यदि सही शक्ति, लगन और इच्छाशक्ति हो, तो असंभव कुछ भी नहीं है. नेपोलियन के अनुसार भी असंभव शब्द तो सिर्फ मूर्खों के शब्दकोष में ही मिलता है. यदि किसी में दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तो कुछ भी हो सकता है. आज राष्ट्रीय विकास और प्रगति के कार्य असंभव भी नहीं हैं, बशर्ते उन्हें पूरी निष्ठा, ईमानदारी सच्चाई, लगन और बिना किसी पक्षपात के साथ इन्हें पूरा किया जाये. मोदी सरकार की दूसरी पारी से कुछ ऐसी ही आशाएं और अपेक्षाएं जनता को है.

वेद मामूरपुर, नरेला

शपथ ग्रहण के संदेश

लोक सभा चुनावों में मिले प्रचंड बहुमत के बाद मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आगाज करने जा रही है. इस बार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता न देकर नयी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वह आतंकपरस्त पाकिस्तान को लेकर किसी प्रकार के भ्रम में नहीं है. पाकिस्तान के साथ ही पूरी दुनिया को इस तरह से स्पष्ट संदेश भी दे दिया है. दूसरी तरफ, बिम्सटेक के सदस्य देशों को न्योता देकर मोदी जी ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और पुराने सार्क सहयोगियों को एक साथ साधने की कोशिश की है. उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार अपने इस दूसरे कार्यकाल में जनता के सभी वर्गों के विकास के लिए समभाव से काम करती रहेगी.

चंदन कुमार, देवघर

कुछ अलग

बाग में बहार ऐसे आती है

संतोष उत्सुक
वरिष्ठ व्यंग्यकार
santoshutsuk@gmail.com

शहर के सवा सौ साल पुराने बाग में बच्चे, जवान और बुजुर्ग सुबह शाम सैर करने आते हैं. गर्मी का मौसम परेशान करता है, तो सैर करनेवाले बढ़ते जाते हैं. नगरपालिका ने 'स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत' अभियान के निमित स्वच्छता नियमों का पालन करवाने के लिए बाग में अनेक स्थानों पर रंगीन व बड़े विज्ञापन लिखवाकर जिम्मेदारी बढ़िया तरीके से निभायी.

उस बाग में बहार लाने का जिम्मा हाल ही में हुए चुनावों में जीते हुए राजनीतिक और कुछ समझदार सरकारी लोग लेने लगे, तो वहां लोहा, ईंट, रेत व सीमेंट के ढेर लगने लगे. जख्मी हुई हरी घास ने बाग के मैदान में दौड़ लगाते नौजवान से कहा कि उसके ऊपर कई दिन बजरी पड़ी होने के कारण जान निकली जा रही है, कृपया कुछ करो. नौजवान ने सत्य बोला, मेरे पास जरा भी समय नहीं है, क्योंकि मुझे आज स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में सबसे तेज भागकर मेडल जीतना है.

वहीं दूसरी क्यारी में पूजा के लिए फूल तोड़ती महिला से सारे पौधे बोले- हमारे ऊपर रेत गिरा दिया गया है, सांस नहीं आ रही है, कुछ पौधे ईंटों की चोट से मर गये हैं, हमारी मदद कर दो बहन. इस पर महिला ने कहा कि मंदिर में जल्दी पूजा करने के बाद घर जाकर मैंने अपने इकलौते पुत्र के लिए आलू-प्याज के परांठे बनाने हैं, तुम्हारे लिए मेरे पास समय नहीं है.

कुछ बुजुर्ग, उजड़ती क्यारियों के पास बेंच पर बैठे हुए थे और काफी देर से बाग की दुर्दशा पर चर्चा कर रहे थे. लंबी डाली वाले कुछ उदास पौधों ने मौका देखकर अपना दुख संप्रेषित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

बेंच पर बैठे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने कहा- सेवानिवृत्ति के बाद अब हमारे पास काफी समय है, तो हमें मिलकर इस ऐतिहासिक बाग को हरा-भरा रखने के लिए कुछ संजीदा प्रयास करने चाहिए. उन्होंने देखा कि बाग में भौतिक विकास के लंबे वृक्ष, बड़े आकार के फूल, आजीवन हरे रहनेवाले पौधे लगाये गये हैं. बाग के एक हिस्से में कितने ही सरकारी दफ्तर खोल दिये गये हैं, ताकि उनसे नगर पालिका को कुछ और किराया आ सके. यहां-वहां पत्थर और कूड़ा फैला हुआ है, जिसे कर्मचारी रोज 'उठाते' हैं.

बाग के बीच में बना तालाब चीखता रहता है कि लोग मेरे अंदर कचरा फेंकते हैं. पुराने बंद सुंदर फव्वारे के चारों तरफ लगी सीमेंट में जकड़ी लोहे की ग्रिल उसकी स्थायी रक्षा कर रही है. बाग के एक क्षेत्र में लोहे की मोटी ग्रिल के चार गेट लगा दिये हैं और नालियों के ऊपर लोहे के जाल बिछा दिये गये हैं, ताकि उनके नीचे से ठेकेदारी का पानी आराम से बह जाये.

बाग में रोशनी का अंधकारमय इंतजाम किया गया है. पुरानी दर्जनों लाइटें ठीक न करके ऊंची, महंगी दूर तक रोशनी देनेवाली लाइट एक 'खास' से सप्लाई करवा दी गयी है. बुजुर्ग समझ गये हैं कि जब हर मामले के मंच पर राजनीति का नंगा नाच चल रहा हो, तो चुप रहना बेहतर है. सभी बुजुर्ग थोड़ी देर शांत रहे, फिर अपने-अपने घर की ओर चल दिये.

देश दुनिया से

चीनी न्यूरोसाइंटिस्ट का अमेरिका से निष्कासन

चीन-अमेरिकी संबंधों में हाल में और कड़वाहट घुली है. इस बार वाशिंगटन ने प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को निशाने पर लिया है. इसका ताजा उदाहरण अटलांटा में एमोरी विश्वविद्यालय से दो चीनी न्यूरोसाइंटिस्टों का निष्कासन और अमेरिकी प्रयोगशाला में शोध कर रहे चार पोस्टडॉक्टरल छात्रों का निर्वासन है. ट्रंप प्रशासन को लगता है कि चीन के साथ अकादमिक क्षेत्र में सहयोग करना दुश्मन का वित्त पोषण करना है. इससे अमेरिकी राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे. इसलिए इसे रोकने की आवश्यकता है. हालांकि, येल विवि के अध्यक्ष पीटर सालोवे ने 23 मई को एक खुला पत्र लिखा था कि अमेरिका-चीन संबंधों में तनाव और शैक्षणिक आदान-प्रदान पर बढ़ती निगरानी ने येल और देश के दूसरे विश्वविद्यालयों के अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विद्वानों को बेचैन कर दिया है. उन्होंने अमेरिकी एजेंसियों से अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक आदान-प्रदान के बारे में चिंताओं को स्पष्ट करने का आग्रह भी किया है. इस पत्र में लिखे वक्तव्यों से यह स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में चीन को लेकर अमेरिकी सरकार का हालिया कदम सत्ता का दुरुपयोग है. अमेरिकी सुरक्षा के लिए कथित खतरे का रोना असल में चीन को नीचा दिखाने का बहाना है.

सॉन्ग ग्योयू

कार्टून कोना

साभार : बीबीसी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है